Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, JAN-FEB, 2022, VOL- 9/69

झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति का एक अध्ययन – स्कूल सुविधा एवं उपयोगिता के विशेष संदर्भ में

अर्चना शर्मा, Ph. D.

प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शा. म. ल. बा. कन्या स्ना. महाविद्यालय, इन्दौर

Paper Received On: 21 FEB 2022
Peer Reviewed On: 28 FEB 2022
Published On: 1 MAR 2022

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना (Introduction)

अच्छी शिक्षा पर हर व्यक्ति का अधिकार होता है, जो जीवन में आगे बढ़ने व सफलता प्राप्त करने के लिये बहुत आवश्यक है। स्कूली शिक्षा जीवन की नींव तैयार करती है। यह जीवन के कठिन समय में चुनौतियों का सामना करने में सहायक होती है। पूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान व्यक्ति को जीवन में आत्मनिर्भर बनाता है। यह जीवन में बेहतर संभावनाओं को प्राप्त करने हेतु विभिन्न अवसरों के मार्ग खोलती है, जिससे कैरियर के विकास को बढ़ावा मिलता है। अच्छी शिक्षा जीवन के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करती है जैसे व्यक्तिगत उन्नति, सामाजिक स्तर का विकास, सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार, आर्थिक, सामाजिक स्तर का विकास, सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता व पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान आदि। आधुनिक शिक्षा प्रणाली अशिक्षा, असमानता व गरीबी हटाने में सक्षम है। शिक्षा सभी मानव अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्त्तव्यों व दायित्वों को समझने में हमारी सहायता करती है।

झाबुआ म. प्र. का एक जनजातीय बहुल इलाका है। यहाँ मुख्यतः भील, भिलाला व पटेलिया आदिवासी जातियों रहती है। यह आर्थिक व सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़ी हुई जनजातीयाँ है। जिले में 2011 में साक्षरता का स्तर 44.5% है, जो देश की साक्षरता स्तर 74.04% से अत्यंत कम है। जिले में 2001 में साक्षरता स्तर 41.4% था, जिसमें 10 वर्षों के पश्चात् मात्र 3% की वृद्धि हो सकी है, इसके साथ ही निम्न साक्षरता होने के साथ–साथ लैंगिक

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

असमानता भी बहुत ज्यादा है। यहाँ 5 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 46% के लगभग है, अर्थात अभी भी 54% बच्चे स्कूल में दाखिला नहीं लेते। जो बच्चे स्कूल पहुंचते भी हैं, उनसे मात्र 9.7 प्रतिशत बच्चे ही मिडिल स्कूल तक पहुंच पाते हैं। इस आदिवासी समाज में साक्षरता को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई गई, बहुत से स्कूल खोले गए।

जनजातीय स्कूली विद्यार्थियों हेतु विभिन्न योजनाएं –

जनजातीयों के शैक्षणिक उत्थान हेतु आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 89 आदिवासी विकासखंडों में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूलों के साथ ही अतिरिक्त विशिष्ट स्कूलों का संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में जनजातीय विद्यार्थियों हेतु 23 क्रीड़ा परिसरों की स्थापना भी की गई है। जनजातीय विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना, आवास सहायता, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन, सायकिल योजना मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों हेतु विभिन्न छात्रावास योजनाएं भी संचालित की जा रही है, जिनमें आश्रम, जूनियर छात्रावास, सीनियर छात्रावास व उत्कृष्ठ छात्रावास योजनाएं स्कूली विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध है। म.प्र. में 1083 आश्रम शालाओं में कक्षा 01 से 05 व कक्षा 06 से 08 तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। म.प्र. सरकार द्वारा 199 जूनियर छात्रावासों में कक्षा 06 से कक्षा 08 तक के छात्र व छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

सरकार के द्वारा आदिवासी समाज की शिक्षा हेतु बड़ा बजट बनाया गया, लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं आए। अतः इस समुदाय की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारणों का अध्ययन करने हेतु यह विषय शोध कार्य के लिए चुना गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. जनजातीय परिवारों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना
2. जनजातीय परिवार के बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. जनजातीय परिवार की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
4. जनजातीय क्षेत्र में स्थित स्कूलों में विभिन्न सुविधाओं व उपयोगिताओं का अध्ययन करना।
5. शिक्षा प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।
6. जनजातीय विद्यार्थियों की निम्न शैक्षणिक स्थिति के कारणों का अध्ययन करना।
7. अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सुझाव देना।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शोध समस्या

झाबुआ जिला मूलतः आदिवासी जिला है, इसका क्षेत्रफल 3600 वर्ग कि.मी. है। यहाँ प्रमुख रूप से भील, भिलाला व पटेलिया जनजातीयां निवास करती हैं। झाबुआ जिले में पांच तहसीलें शाजापुर, थांदला, पेटलावद, झाबुआ, मेघनगर है। झाबुआ जिले की जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,24,091 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,14,830 व महिलाओं की संख्या 5,09,261 है। जिले में साक्षरता का स्तर 2011 के अनुसार 44.5% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 54.65% व महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 34.29% है, जो भारत की साक्षरता की तुलना में अत्यंत कम है।

DSE के अनुसार कक्षा I-II तक के विद्यार्थियों जो अक्षर या शब्द पढ़ पाते हैं उनका प्रतिशत 59.1% है। कक्षा I-II तक के विद्यार्थी जो 1–9 तक की संख्या पहचान पाते है उनकी संख्या 62% है। कक्षा III-IV तक के विद्यार्थी जो पढ़ जाते हैं, उनका प्रतिशत 33.4 है। कक्षा IV-V तक के विद्यार्थी, जो जोड़ व घटाना जानते हैं, उनका प्रतिशत 25.1 है।

झाबुआ जिले में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1982 है, माध्यमिक स्कूलों की संख्या 424, हायर सैकेण्डरी स्कूलों की संख्या 58, हाई स्कूलों की संख्या 63, मिडिल व हाईस्कूल की संख्या 6 है। झाबुआ जिले में स्कूलों की कुल संख्या 2533 है।

जिले में स्कूलों की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद जिले में छात्रों की निम्न शैक्षणिक स्थिति मुख्य शोध समस्या है। निम्न शैक्षणिक स्थिति के कारणों का अध्ययन करना व स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं व उनकी उपयोगिता का अध्ययन करना एक अन्य शोध समस्या है। सरकार के द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन होने के बावजूद वे कौन से कारण हैं, जो जनजातीयों में शिक्षा के प्रति रूझान में कमी लाते हैं। जनजातीयों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्कूलों में विद्यार्थियों के इनरोलमेंट में कमी के कारणों का एक प्रमुख कारण है, स्कूल में उपलब्ध पर्याप्त सुविधाओं का ना होना है। इस परियोजना में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं व उनकी उपयोगिता का पता लगाना मुख्य शोध समस्या है।

परिकल्पनाएं –

1. जनजातीय परिवारों की शैक्षणिक स्थिति व उनके बच्चों की शैक्षणिक स्थिति में कोई सकारात्मक संबंध नहीं है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

2. सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
3. जनजातीय क्षेत्र में स्थित स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं का विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

साहित्य समीक्षा (Overview of Literature)

अनुसूचित जनजातीयों के शिक्षा के संबंध में विभिन्न अध्ययन किए गए।

1. Dana Dunn 1993 Population research & policy review में प्रकाशित शोध पत्र Gender inequality in education and employment in the scheduled castes and tribes in India में प्रकाशित शोध पत्र में भारत में अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं में शिक्षा व विकास के क्षेत्र में किस तरह लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है यह अध्ययन किया गया।
2. K. CHanana 1993 Springer Link प्रकाशित शोध पत्र Accessing higher education, the dilemma at schooling women, minorities, scheduled caster and Scheduled Tribes in Contemporary India में अनुसूचित जाति जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं की उच्च शिक्षा में पहुंच में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया गया है।
3. K. Sujatha 2002 में जनजातीयों के मध्य शिक्षा में अध्ययन किया गया कि जनजातीय विद्यार्थियों में निम्न शिक्षा सहभागीता का कारण निम्न स्वास्थ्य स्तर का होना रहा है, इस कारण से विद्यार्थी स्कूलों का लाभ उठा पाने में असमर्थ रहे हैं। इसके लिए एक दीर्घकालीन योजना का बनाया जाना लाभप्रद होगा।
4. Francois leclercq 2003 में आर्थिक व राजनीतिक समीक्षा में प्रकाशित शोधपत्र Education Guarantee Scheme and Primary Schooling in M.P. में देवास व बेतूल जिले के पब्लिक स्कूलों की फील्ड स्टडी की गई। इस अध्ययन में शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित पब्लिक स्कूलों का अध्ययन किया गया। शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार का ग्रामीण क्षेत्र व पब्लिक स्कूल पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया।
5. सेडवाल, एम कामत 2008 में – "Education and social equity with a special focus on scheduled castes and scheduled tribes in elementary education" Creative Pathology to access Research Monograph No. 19 में अनुसूचित जातियों व जनजातीयों के स्कूल न

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पहुंचने व समान शिक्षा न प्राप्त करने के कारणों का अध्ययन किया गया, जिनकी विभिन्न योजनाओं को बनाने में आवश्यकता होती है।

6. आर. गोविंद, मधुमिता बंदोपाध्याय 2010 Construction for Research on educational access transitions and equity में प्रकाशित शोधपत्र Educational access in M.P. & C.G. - India में म.प्र. व छत्तीसगढ़ के 36 गांवों के 88 स्कूलों जिसमें 9,653 विद्यार्थी पढ़ते थे उनका आनुभाविक अध्ययन किया गया, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं व उनके क्रियान्वयन का विद्यार्थियों के स्कूल पहुंच पर प्रभावों का अध्ययन किया गया।
7. Abhishek Basu 2012 में Education Research and Reviews में Status of educational performance of tribal students - A study in Paschim Mednipur District, West Bengal में पं. बंगाल के मिदनापुर जिले के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन की स्थिति का अध्ययन किया गया वे इस संदर्भ में प्रस्तुत किए गए।
8. Dr. Haseena V. A. and Dr. Ajim P. Mohammad 2014 में International Journal of scientific and Research publication में प्रकाशित शोध पत्र – Scope of education and dropout among tribal students in kerala - A study of scheduled tribes in Attappady में केरल में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में शिक्षा का क्षेत्र व स्कूल छोड़ने के कारणों की स्थिति का अध्ययन किया गया।
9. प्रियम सिंह, लोकेश कुमार 2019 JETIR Volume 6, issue 6 में प्रकाशित शोधपत्र A Review : Impact of Higher Secondary Education on effectiveness of Higher Education of Scheduled Castes and Tribes in India with especial reference to Madhya Pradesh में भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हायर सैकेण्ड्री परीक्षा परिणाम का उनके उच्च शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया। इसमें यह भी अध्ययन किया गया कि समाज का यह वर्ग आर्थिक असमानता व निर्धनता से ग्रसित है, जिनमें लैंगिक असमानताएं भी विद्यमान है, जो उनकी शिक्षा को प्रभावित करता है।

शोध प्राविधि –

इस परियोजना में शोध कार्य हेतु प्रमुख रूप से निर्दशन पद्धति का प्रयोग किया जावेगा। सभी प्रामाणिक द्वितीयक समंकों को इस शोध कार्य का महत्वपूर्ण आधार बनाना जावेगा तथा समस्या के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंकों का संकलन करके अधिकाधिक सही एवं व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया जावेगा।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्राथमिक समंक – प्राथमिक समंक एकत्रित करने हेतु मुख्य रूप से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग किया जावेगा। इसके अन्तर्गत शोध क्षेत्र में उपस्थित होकर न्यादर्श इकाइयों से संपर्क किया जावेगा, जिससे समंक अधिक प्रामाणिक शुद्ध तथा विश्वसनीय हों साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्र किए जावेगें।

द्वितीय समंक – द्वितीय समंक एकत्रित करने हेतु सरकारी प्रकाशन, जिला सांख्यिकीय प्रकाशन, अर्द्ध सरकारी प्रकाशन, समिति एवं आयोग के प्रतिवेदन समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन इत्यादि का प्रयोग किया जावेगा।

सारणीयत एवं विश्लेषण – समंक संकलन के पश्चात् उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग से समंकों का विश्लेषण किया जावेगा।

अध्ययन का क्षेत्र – पश्चिमी मध्यप्रदेश का झाबुआ जिले के तीन ग्राम अध्ययन का क्षेत्र होगें।

अध्ययन की इकाई – चयनित गांव से एक एक जनजाति परिवार जिसके बच्चे 5 वर्ष से 20 वर्ष के मध्य है, अध्ययन की इकाई होगा।

शोध अध्ययन

झाबुआ जिला जनजातीय बहुल इलाका है। भौतिक संस्कृति की अंधी दौड़ से दूर जनजातियाँ आज भी अपने परम्परागत रहन–सहन, खान–पान व रूढ़िवादी कृषि प्रणाली में जकड़ी हुई है। यह समाज रूढ़िवादी विचारों, अंधविश्वासों से आबद्ध है। यहाँ गरीबी का स्तर सर्वाधिक है, यहाँ की ग्रामीण जनजातियाँ गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करती है। जनजातीय समाज का विकास शिक्षा के विकास से जुड़ा हुआ है। स्कूली शिक्षा के विकास से इस समाज की नई पीढ़ी का विकास संभव है। सरकार के द्वारा इस समाज के विकास हेतु अनेक योजनाएं लाई गई है। 2019–20 के बजट में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए बजट में 28% की वृद्धि की गई है। इन जनजातियों के विकास के लिए बजट में सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही है, जिले में स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि की गई, लेकिन इसके बावजूद जनजातियों में शिक्षा के प्रति रूचि जागृत नहीं हुई। इस अध्ययन में जिले के तीन ग्रामों कालापान, लम्बेला व बेबरवड़ी में स्कूली जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति जिसमें स्कूल सुविधा व उपयोगिता से संबंधित 50 परिवारों का सर्वेक्षण निम्नानुसार किया गया :–

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सारणी क्र. 1

माता–पिता की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन

शैक्षणिक स्थिति	माता	प्रतिशत %	पिता	प्रतिशत %
निरक्षर	46	92	41	82
प्राथमिक	4	8	5	10
माध्यमिक	–	–	3	6
हायर सेकेण्ड्री	–	–	1	2
कुल सर्वेक्षित	**50**	**100**	**50**	**100**

स्त्रोत – सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि सर्वेक्षित माताओं में 92% निरक्षर व 8% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। सर्वेक्षित पिताओं में 82% निरक्षर, 10% प्राथमिक, 6% माध्यमिक व 2% हायर सेकेण्ड्री पास हैं।

सारणी क्र. 2

परिवारों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

आर्थिक स्थिति (वार्षिक आय)	सर्वेक्षित संख्या	प्रतिशत
1,000–5,000	8	16%
5,000–10,000	8	16%
10,000–20,000	18	36%
20,000 से अधिक	16	32%
कुल सर्वेक्षित	**50**	**100**

स्त्रोत – सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि 16% परिवारों की आर्थिक आय 1,000/– से 5,000/– वार्षिक है। 16% परिवारों की वार्षिक आय 5,000/– से 10,000/– के बीच है। 36% परिवारों की वार्षिक आय 10,000/– से 20,000/– के बीच है व 32% परिवारों की वार्षिक आय 20,000/– से अधिक है, अर्थात् ज्यादातर परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।

सारणी क्र. 3

परिवार की व्यवसायिक स्थिति

परिवार का व्यवसाय	सर्वेक्षित संख्या	प्रतिशत
स्वयं की कृषि भूमि	49	98
कृषक मजदूर	01	2
वन आधारित व्यवसाय	–	–
अन्य व्यवसाय	–	–
कुल संख्या	**50**	**100**

स्त्रोत – सर्वेक्षण

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि सर्वेक्षित परिवारों में से 98% परिवार अपनी आजीविका के लिए स्वयं की भूमि पर आधारित है, 2% परिवार कृषक मजदूर है।

सारणी क्र. 4

परिवार में बच्चों की संख्या की स्थिति

परिवार में बच्चों की संख्या	सर्वेक्षित संख्या	प्रतिशत
1	1	2
2	4	8
3	9	18
4	10	20
4 से अधिक	26	52
कुल परिवार	**50**	**100**

स्त्रोत – सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि 52% परिवारों में बच्चों की संख्या 4 से अधिक, 20% परिवारों में बच्चों की संख्या 4, व 18% परिवारों में बच्चों की संख्या 3, 8% परिवारों में बच्चों की संख्या 2 है। केवल 2% परिवारों में बच्चों की संख्या 1 है।

सारणी क्र. 5

स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों की स्थिति

अध्ययनरत बच्चों की स्थिति	सर्वेक्षित संख्या	प्रतिशत
प्राथमिक	20	40
माध्यमिक	25	50
हाई स्कूल	3	6
इंटर मीडियट	2	4
कुल परिवार	**50**	**100**

स्त्रोत – सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि प्राथमिक अध्ययनरत बच्चों का प्रतिशत 40 है, माध्यमिक, हाईस्कूल व इंटर मीडियट में अध्ययनरत बच्चां का प्रतिशत क्रमशः 50, 6 व 4 है।

सारणी क्र. 6

स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति

स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं	परिवार की स्वीकारोक्ति	प्रतिशत
स्वच्छ जल	32	64
शौचालय	28	56
स्वच्छ कक्षा	24	48
खेल का मैदान	26	52
कम्प्यूटर	–	–
लैब	–	–

स्त्रोत – सर्वेक्षण

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि स्कूलों में स्वच्छ जल की उपलब्धता 64% परिवारों द्वारा बताई गई है, 56% परिवारों द्वारा शौचालय की उपलब्धता, 48% परिवारों द्वारा स्वच्छ कक्षा व 52% परिवारों द्वारा खेल के मैदान की उपलब्धता बताई गई है। कम्प्यूटर व लैब की उपलब्धता किसी परिवार द्वारा नहीं बताई गई है।

सारणी क्र. 7

स्कूलों में अध्यापकों की उपलब्धता

स्कूलों में विषयवार अध्यापकों की उपलब्धता	**सर्वेक्षित परिवार**	**प्रतिशत**
गणित	29	58
अंग्रेजी	12	24
विज्ञान	18	36
सामाजिक विज्ञान	40	80

स्त्रोत – सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि 58% परिवारों द्वारा गणित के, 24% परिवारों द्वारा अंग्रेजी के, 36% परिवारों द्वारा विज्ञान के व 80% परिवारों द्वारा सामाजिक विज्ञान के अध्यापक की उपलब्धता की जानकारी दी गई है।

सारणी क्र. 8

सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी का विवरण

सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी	**सर्वेक्षण**	**प्रतिशत**
हाँ	03	06
नहीं	47	94
कुल परिवार	**50**	**100**

स्त्रोत – सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि 06% परिवारों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी है, जबकि 94% परिवारों को किसी प्रकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सारणी क्र. 9

स्कूल के प्रति रूझान की स्थिति का विवरण

स्कूल न जाने का कारण	सर्वेक्षित परिवार	प्रतिशत
रूचि का अभाव	–	–
दूरी	–	–
उपलब्ध सुविधाओं का अभाव	50	100
अन्य कारण	–	–
कुल परिवार	**50**	**100**

स्त्रोत – सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अभाव के कारण जनजातीय विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं।

सारणी क्र. 10

पढ़ाई बीच में छोड़ने के कारण का विवरण

पढ़ाई बीच में छोड़ने का कारण	सर्वेक्षित परिवार	प्रतिशत
रूचि का अभाव	–	–
पारिवारिक जिम्मेदारी	01	02
पलायन	49	98
अस्वस्थता	–	–

स्त्रोत – सर्वेक्षण

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, कि 98% परिवारों द्वारा पलायन किए जाने के कारण बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं जबकि 2% परिवार – पारिवारिक जिम्मेदारी को इसका कारण मानते हैं।

निष्कर्ष –

इस शोध पत्र में जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया गया, जिसमें स्कूल सुविधा व उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण किया गया, जिससे निम्न निष्कर्ष स्पष्ट हुए –

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न पाया गया लगभग 88% पालक निरक्षर पाए गए, लगभग 7.5% पालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त थे व लगभग 4.5% पालक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व 2% पालक हायर सेकेण्ड्री शिक्षा प्राप्त पाए गए, जिससे जनजातीय विद्यार्थियों की निम्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि का पता चलता है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सर्वेक्षण के दौरान जनजातीय परिवारों की निम्न आर्थिक स्थिति का पता चलता है, अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वे दो वक्त की रोटी से आगे सोच ही नहीं पाते, उनका जीवन अत्यंत कठिनाईयों व असुविधाओं से भरा है।

ज्यादातर परिवारों के पास स्वयं की कृषि भूमि है। वे अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्य परम्परागत तरीके से करने के कारण वे सही मात्रा में उपज नहीं प्राप्त कर पाते, जिसके कारण वे गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।

जनजातीय परिवारों की गरीबी का एक कारण बड़ा परिवार होना है। इन गांवों में ज्यादातर परिवार में 4 से अधिक बच्चे पाए गए। इन परिवारों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव पाया गया, जिसके कारण वे अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा–दीक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं, उनमें सभी विषयों के अध्यापकों की उपलब्धता का अभाव पाया गया। अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषय के अध्यापकों की उपलब्धता न होने से विद्यार्थियों में इन विषयों के प्रति रूचि जागृत नहीं हो पाती, इससे उनकी आगे की पढ़ाई बाधित हो जाती है।

सर्वेक्षण के दौरान पाया गया, कि सरकार द्वारा यद्यपि विभिन्न सुविधाएं जैसे स्वच्छ जल, शौचालय, स्वच्छता, खेल का मैदान आदि की व्यवस्था की गई है, लेकिन देखरेख के अभाव में ये सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध न होने के कारण उन्हें विभिन्न तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है विशेषकर छात्राओं को इस कारण से भी स्कूल छोड़ना पड़ता है। सर्वेक्षण में सभी परिवारों द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का अभाव बताया गया, जिसके कारण उनके बच्चों में स्कूल के प्रति रूझान का अभाव पाया जाता है।

परिकल्पना परीक्षण –

1. जनजातीय परिवारों की शैक्षणिक स्थिति व उनके बच्चों की शैक्षणिक स्थिति में सकारात्मक संबंध पाया गया है।

   यह परिकल्पना स्वीकार हुई है। सर्वेक्षण के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो पालक अनपढ़ हैं, जो पालक प्राथमिक शिक्षित हैं, उनके बच्चे माध्यमिक शिक्षित हैं, जो पालक हाईस्कूल या इंटरमीडियट शिक्षित हैं, उनके बच्च भी उस शिक्षा स्तर तक शिक्षित हैं। अतः

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

जनजातीय परिवारों की शैक्षणिक स्थिति व उनके बच्चों की शैक्षणिक स्थिति में सकारात्मक संबंध पाया गया है।

2. सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

   सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया, कि लगभग 94% पालकों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी नहीं है, क्योंकि वे शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। अतः सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

3. जनजातीय क्षेत्र में स्थित स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं का विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

   यह परिकल्पना स्वीकार हुई है। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया, कि सरकार द्वारा उपलबध सुविधाएं देखरेख के अभाव में सही कार्य नहीं कर पा रही है, अतः उन उपलब्ध सुविधाओं का सही उपयोग नहीं हो पाने के कारण विद्यार्थी उनसे लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, इस कारण विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

समस्याएं –

1. **परिवार की निम्न शैक्षणिक स्थिति** – जनजातीय परिवारों की निम्न शैक्षणिक स्थिति का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। सर्वेक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 88% पालक निरक्षर पाए गए, जिसके कारण वे शिक्षा का महत्व अपने बच्चों को नहीं समझा पाते हैं। इसके कारण विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है।
2. **निम्न आर्थिक स्थिति** – निम्न आर्थिक स्थिति भी बच्चों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बाधक तत्व है। सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करते हैं, जिसके कारण वे अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते।
3. **परिवार नियोजन न होना** – सर्वेक्षण के दौरान पाया गया, कि जनजातीय परिवार परिवार नियोजन के प्रति जागरूक नहीं हैं, जिसके कारण लगभग 90 परिवारों में 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं, जिससे वे अपने बच्चों का सही पालन पोषण व उचित शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पाते। यही कारण उनके गरीबी रेखा से रेखा नीचे रहने का है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

4. **शिक्षा का महत्व न समझना** – माता–पिता के निरक्षर होने के कारण वे शिक्षा का महत्व नहीं समझते इसलिये सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाने के बाद भी समाज में शिक्षा के प्रति रूचि का अभाव है।
5. **स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग न होना** – यद्यपि सरकार द्वारा स्कूलों में स्वच्छ जल, शौचालय, स्वच्छ कक्षा, खेल का मैदान आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन उनकी सुचारू देखरेख न होने के कारण विद्यार्थियों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता, जिसके कारण लगभग सभी परिवारों द्वारा सुविधाओं की उपलब्धता का अभाव बताया गया है।
6. **विषयवार अध्यापकों की उपलब्धता न होना** – ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में विभिन्न विषयों के अध्यापकों की उपलब्धता का अभाव पाया गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों में विषय के प्रति रूचि का अभाव पाया जाता है।
7. **सरकारी योजनाओं की जानकारी न होना** – सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के जनजातीय परिवारों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते, व विभिन्न योजनाओं के लाभ से विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं।
8. **पलायन** – सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया, कि गांवों में आज भी बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने का एक बड़ा कारण पलायन है। जनजातीय परिवारों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि है और कृषि में वर्षभर रोजगार नहीं प्राप्त होता है इसलिये वे कुछ समय के लिए शहरों की ओर रोजगार हेतु पलायन करते हैं, जिसके कारण उनके बच्चों को स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ता है।

सुझाव –

1. **जनजातीय समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करना** – इस समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाए जाने की आवश्यकता है, इसके लिए एन.जी.ओ. व अन्य सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें शिक्षा के महत्व को बताया जाना चाहिए जिससे वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके।
2. **आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाना** – जनजातियाँ अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहती है, कृषि के अतिरिक्त उन्हें वैकल्पिक

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

रोजगार जैसे – पशुपालन, मुर्गीपालन, व अन्य कुटीर उद्योगों के संबंध में प्रशिक्षण व वित्त सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

3. **परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहन** – इन जनजातियों को छोटे परिवार के लाभ बताकर परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार परिवार नियोजन हेतु आर्थिक प्रोत्साहन देकर भी इन्हें प्रोत्साहित कर सकती है।
4. **स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाना** – इन ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में स्कूल के प्रति रूचि जागृत हो सके। सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का समय–समय पर देखरेख सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उसका सद्उपयोग हो सके।
5. **विषयवार अध्यापकों की उपलब्धता** – ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में विषयवार अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में विषयों के प्रति रूचि जागृत हो सके। अध्यापकों की उपलब्धता से स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति में भी वृद्धि होगी व उनके शैक्षणिक स्तर में भी सुधार होगा।
6. **सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदाय करना** – सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि लगभग 94% लोगों को सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी नहीं है। अतः इस समाज में योजनाओं की जानकारी प्रदाय की जाना चाहिए। घर–घर जाकर, पंचायत के माध्यम से व वृत्त चित्र के माध्यम से उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदाय की जाना चाहिए।
7. **पलायन को रोकने के प्रयास** – ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी होने से श्रमिकों का पलायन होता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार की सुविधाएं बढ़ाकर पलायन को रोका जा सकता है, जिससे उनके बच्चे सतत स्कूल में उपस्थित रहकर अध्ययन कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Reference)

S. Patel - Tribal education in India – Mittal Publication, New Delhi - First addition 1991, ISBN-81-7099-292-3 2.

Dr. Manjundra DC, Dr. Anjali Kurane, Dr. Steven Wind, Dr. Annapurna - Ignored claims - A Focus on Tribal Education in India, Kalpaz Publications 2006, ISBN-81-7835 679-1

M. Kamat - Education and social equity - with a special focus on scheduled Castes and scheduled Tribes in Elementary Education 2008 https://scholarworks.umass.edu/cie - faculty

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

Francois Ledercq - Education Guarantee Scheme and Primary Schooling in M.P. - Economic & Politically weekly vol 38 No. 19 (May - 10-16-2003 PP. 1855-1869)

R. Govinda and Madhumita Bandyopadhyay Oct. 2010 - Educational Access in Madhya Pradesh and Chhatisgarh - India - CREATE ISBN 0-901881-66-X

http://www.create or pc.org

Amanullah, M - A Report on status of education in tribal areas of Madhya Pradesh 1994 - MP Tribal Research and Development Institute Bhopal (Publisher)

Dana Dunn - Gender inequality in education and employment In the scheduled Castes and tribes of India 1993 Population Research and policy Review 12, 53-70 (1993) http://doi.org/10.1007/BF01074509

S.N. Chaudhary - Tribal Development since Independence 2009 Concept Publishing company ISBN-13-978-81-8069-622-0

Shweta Bagai, Neera Nandi - Tribal Education - A Fine Balance 2009 - Printed at Rakesh Press N. Delhi

Balagopalan, S & Subrahmaniam R. (2003) Dalit & Adivasi children in school : some preliminary research themes and findings IDS Bulletin 34 (1) 43-54

Bapat M.V. (1994) A few thoughts on tribal Education, Vanyajathi Journal pp 54-49.

Gautam V. (2003) Education of tribal 'children in India and issue of medium of Instructions: A Janshalla experience. UN/Government Janshala Programme N. Delhi.

Sujata K. (1994) Educational Development Among Tribes : A study of sub plan Area in Andhra Pradesh New Delhi; South Asian Publication.

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies